तुमकुर का पंचायती राज

पंचायती राज अधिनियम पास हुआ। लोगों की उम्मीदें जागीं। औरतों की भागीदारी राजनीति में सक्रिय रूप से होने की आशा बंधी। पर ऐसा नहीं हुआ। मूल्यांकन से पता चला ज्यादातर चुनाव अभियान पार्टी आधारित थे। लिहाज़ा महिला संगठनों की इनमें कोई भूमिका नहीं थी। सामाजिक बंधनों, पैसे की कमी के कारण भी वे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से सकुचाती हैं। पर कर्नाटक के तुमकुर ज़िले का उदाहरण इससे बिलकुल विपरीत है।

बंगलौर से सौ किलोमीटर दूर स्थित है तुमकुर ज़िला। इस सूखे-पिछड़े इलाके में 1693 औरतें चुनी गई हैं। और इन सभी औरतों को पूरा ज़िला प्रशासन जोर-शोर से सशक्त और जागरूक बनाने में लगा है। आइए देखें, कैसे?

यहां के ज़िला अधिकारियों ने इसके लिए 23 से 26 अक्तूबर तक चार दिनों का कार्यक्रम तय किया। लगभग पचास प्रतिशत घरों को मुख्यालय में बदला गया। साथ ही घरों को अच्छी तरह से सजाया-संवारा भी गया।

ज्यादातर चुनी गई सभी औरतें इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यसूची बनाने, कार्यकर्ता और संपर्क सूत्र जुटाने और कार्यक्रम चलाने तक की व्यवस्था की जिम्मेवारी इलाके के एन.एल.एम. अधिकारियों ने उठाई।

ताक़त का अहसास

औरतें इस कार्यक्रम के प्रति बहुत उत्साहित थीं। कार्यक्रम के दौरान निर्वाचित औरतों के रहन-सहन के विभिन्न तरीकों को लेकर चर्चा हुई। औरतों को लगा कि पंचायती राज में महिलाओं की सीट आरक्षित होने की वजह से उन्हें घर-बाहर की दुनिया देखने-समझने का मौका मिला। कई औरतों का कहना था कि अगर आरक्षण वापस भी ले लिया जाए तब भी वह अपने अधिकार वापस लेंगी। पुरुषों से मुकाबला करेंगी। बिना आरक्षण चुनाव लड़ेंगी।

उन्हें लगा कि वे भी पुरुषों की तरह काम कर सकती हैं। आरक्षण से उन्हें जो मौका मिला है उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाकर उसका सदुपयोग वे ज़रूर करेंगी। यह ज़िम्मेवारी बोझ न बन जाए या फिर थोड़े दिन के बाद उनका उत्साह ठंडा न पड़ जाए, इसलिए वे इसके लिए अलग से समय निकालती हैं। घर का काम जल्दी से निपटा कर बैठक में आती हैं। बैठक में समय से पहुंचने के लिए काम छोड़ भी देती हैं।

विरोध का सामना

ऐसा नहीं है कि इन औरतों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। एक औरत ने बताया कि शुरू में उसके पति ने उसे पंचायती राज की सदस्या बनने के लिए उत्साहित किया। पर जब देखा कि वह सक्रिय हो गई तब उसे रोकने की कोशिश करने लगे।

ग्राम सभा की महिलाओं को भी पंचायत सदस्याओं से शिकायत है। उनका मत है कि सभी सदस्य वोट तो मांगते हैं पर बदले में कुछ नहीं करते। इस टिप्पणी से एक पंचायत सदस्या बहुत शर्मिंदा हुई। बाद में उन्होंने अपने खर्चे से सड़क पर बिजली लगवाई।

एक अन्य औरत का कहना है कि भाषा न समझ पाने के कारण उनके पति उनके साथ सभी बैठकों में जाते हैं। इसी गांव में एक हरिजन निर्वाचित महिला को अध्यक्षा ने बहुत दबा-धमका कर रखा था। यह अध्यक्षा भी हरिजन थी, पर पढ़ी-लिखी और वाचाल।

फिर भी पंचायत की सदस्याएं सजग, सचेत लगीं। पंचायत के सातों गांवों में उन्होंने ग्राम सभा की बैठक आयोजित की। ये औरतें मेधावी और मुखर हैं। पर पूरी तरह पंचायत के और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी उन्हें मुहैया नहीं थी। देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा है, इस पर भी उनके पास कोई खबर नहीं थी।

फिर भी कार्यक्रम की गतिशीलता और कोशिशों को नज़र-अंदाज नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम से औरतों में आपसी स्नेह और आत्मीयता बढ़ी है। जो औरतें इस बार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकीं उन्होंने निश्चय किया कि वे अगली दफा इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगी। जो इस बार चुनाव में नहीं खड़ी हुईं वे अगले साल चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। □

जानकारी साभार ISST
समाचार पत्रिका से